

मंत्री टेटवाल ने वीरगति प्राप्त जवान नागर को दी श्रद्धांजलि

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने जम्मू-कश्मीर में देशसेवा के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए राजगढ़ जिले के ग्राम टूटियाहेड़ी निवासी भारतीय सेना के जवान हरिओम नागर को मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। मंत्री टेटवाल ने स्व. नागर की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजन से भेंट कर उन्हें ढाढस बंधाया। मंत्री टेटवाल ने कहा कि हरिओम नागर जैसे साहसी और राष्ट्रनिष्ठ सपूतों के कारण ही भारत की आत्मा जीवित रहती है। उनका बलिदान समूचे राष्ट्र का गौरव है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ हर कदम पर खड़ी है। शहीद हरिओम नागर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये गाँव में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राजगढ़ जिले के पंचो नगर से टूटियाहेड़ी तक शहीद की अंतिम यात्रा में अपार जन सैलाब उमड़ा। %भारत माता की जय% और %शहीद हरिओम नागर अमर रहें% के नारों से गुंजते माहील में पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। जगह-जगह पुष्पवर्षा कर श्रद्धांजलि दी गई। महिलाएँ, युवा, बुजुर्ग और बच्चों ने भावविभोर होकर नम आंखों से अंतिम दर्शन किए। ग्राम टूटियाहेड़ी में सेना की टुकड़ी द्वारा सैन्य परंपराओं के अनुसार शहीद नागर को अंतिम सलामी दी गई। तिरों में लिपटी पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। हवाई फायरिंग, राष्ट्रान और मौन श्रद्धांजलि के साथ पूरे गाँव ने शहीद हरिओम नागर को अंतिम विदाई दी। मंत्री टेटवाल ने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि शहीदों का सम्मान केवल श्रद्धांजलि तक सीमित न हो, बल्कि उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात करते हुए हमें अपने कर्तव्यों और नागरिक उत्तरदायित्वों को भी निभाना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सांसद रोडमल नागर, विधायक अमर सिंह, ज्ञान सिंह गुर्जर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी और हजारों की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

वन विभाग ने जल गंगा संवर्धन अभियान में 5 करोड़ से अधिक पौधों का किया रोपण

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रदेश को हरा-भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के आव्हान पर वन विभाग द्वारा प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान में जैव विविधता को बढ़ावा देने, पर्यावरण संतुलन बनाये रखने, जलवायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और जल संचय करने के उद्देश्य से 71 हजार 682 हेक्टेयर में 5 करोड़ 35 हजार 872 पौधों का रोपण किया गया है। अभियान में 78 हजार 665 हेक्टेयर में कुल 5 करोड़ 25 लाख 40 हजार 158 पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया था। अभी तक लक्ष्य के विरुद्ध 95.23 प्रतिशत पौधरोपण किया जा चुका है। वन विभाग की विभिन्न शाखाओं द्वारा पौधरोपण के लक्ष्य के विरुद्ध अनुसंधान एवं विस्तार शाखा द्वारा 115 हेक्टेयर में 82 हजार 108, बेम्बो मिशन में 1113 हेक्टेयर में 4 लाख 9 हजार 735, कैम्पा में 50 हजार 545 हेक्टेयर में 3 करोड़ 25 लाख 72 हजार 688, डेवलपमेंट में 12 हजार 903 हेक्टेयर में 67 लाख 86 हजार 151, ग्रीन इण्डिया मिशन में 1413 हेक्टेयर में 4 लाख 69 हजार 515, लघु वनोपज संघ में 1854 हेक्टेयर में 9 लाख 33 हजार 875 और वन विकास निगम द्वारा 3 हजार 521 हेक्टेयर में 87 लाख 81 हजार 800 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया।

मध्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को 1498.62 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली अटल गृह ज्योति योजना का प्रदेश में प्रभावी और पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 30 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को करीब 1498 करोड़ 62 लाख रूपए से अधिक की सब्सिडी दी गई है।

हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह 24 से 29 जुलाई तक एवं नाट्यशास्त्र पर केन्द्रित भरतमुनि राष्ट्रीय संगोष्ठी 25 से 28 जुलाई तक

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के समन्वय से प्रकृति और भारतीय संस्कृति के प्रति आभार प्रकट करने के मूल भाव के साथ हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह एवं नाट्यशास्त्र पर केन्द्रित भरतमुनि राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह अनूठा अवसर होगा जब देश के सुप्रसिद्ध रंगगुरु, रंगकर्मी, रंग विशेषज्ञ एक स्थान पर एकत्रित होंगे। हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन 24 से 29 जुलाई, 2025 तक रवीन्द्र भवन के हंसध्वनि एवं अंजनी सभागार में और भरतमुनि राष्ट्रीय संगोष्ठी 25 से 28 जुलाई, 2025 तक रवीन्द्र भवन के गौराजन्नी सभागार में आयोजित की जाएगी। समारोह के सम्बन्ध में राज्यमंत्री लोधी मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में

प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर संचालक, संस्कृति एन.पी. नामदेव और मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक संजय श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। राज्य मंत्री लोधी ने बताया कि यह समारोह कला और विचारों की एकता को दर्शाने वाला समारोह है। रंगमंच में विविधता के बीच संतुलन और संवाद का संदेश देता है। इस नाम से समारोह न केवल थिएटर का उत्सव होता है, बल्कि यह सांस्कृतिक समरसता, आध्यात्मिक गहराई और राष्ट्रीय विचारधारा की अभिव्यक्ति भी बन जाता है। इसके साथ ही श्रावण मास में हरियाली का उत्सव प्रकृति के पुनर्जीवन और मानव जीवन से गहरा जुड़ाव भी दर्शाता है। यह उत्सव हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करने की भी प्रेरणा देता है। इसी प्रेरणा के भाव से हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 24 जुलाई को

इस समारोह का शुभारंभ भी हरियाली अमावस्या के दिन किया जा रहा है। राज्य मंत्री लोधी ने बताया कि नाट्यशास्त्र पर केन्द्रित भरतमुनि राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य संस्कृति विभाग द्वारा स्थायी कार्य करना है। मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग प्रदेश एवं देश में वर्षभर अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करता है। जिसमें राज्य की कला एवं संस्कृति के दर्शन के साथ ही उत्कृष्ट प्रतिभाओं की भी अवसर प्राप्त होता है। संस्कृति विभाग द्वारा बीते कुछ वर्षों से यह भी प्रयास किया जा रहा है कि आकादमिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाए, ताकि स्थायी कार्य हो सके। नाट्यशास्त्र पर आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय संगोष्ठी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस संगोष्ठी में देश के सुविख्यात रंगकर्मी एवं नाट्य विशेषज्ञों के वक्तव्य होंगे। साथ ही नाट्य के क्षेत्र में शोध कर रहे शोधार्थी भी सम्मिलित होंगे।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विभागीय सलाहकार समिति की बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष बल देते हुए अभियंताओं के कौशल विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय अभियंताओं को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाए, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण निर्माण तकनीकों और नवीनतम इंजीनियरिंग विधाओं से परिचित हो सकें। बैठक में सलाहकार समिति सदस्य प्रशांत पोल, प्रक्रांत सिंह तोमर, प्रमुख सचिव

लोक निर्माण विभाग सुखवीर सिंह, प्रबंध संचालक एमपीआरडीसी भरत यादव, प्रबंध संचालक भवन निर्माण सी.बी. चक्रवर्ती सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री सिंह ने ‘लोकपथ’ मोबाइल ऐप पर प्राप्त जन-शिकायतों की समीक्षा करते हुए

निर्माण एवं उन्नयन की दीर्घकालिक रणनीति पर भी गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई। मंत्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक निर्माण का मूल उद्देश्य जन-कल्याण होना चाहिए, इसलिए योजनाओं का निर्माण आमजन की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक परियोजना ऐसी हो जो जनता को सुगमता, सुविधा और सुरक्षा प्रदान कर सके। उपस्थित अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं और प्रस्तावों पर विस्तार से जानकारी दी और निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा तकनीकी उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

पंचायत उप निर्वाचन में हुआ 70.51 प्रतिशत मतदान

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। पंचायत उप निर्वाचन 2025 में त्रि-स्तरीय पंचायतों में रिक पद के लिये मंगलवार को मतदान हुआ। सरपंच पद के लिये 49 और जनपद पंचायत सदस्य के 5 पदों के लिये मतदान हुआ। कुल 70.51 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने बताया कि खास बात यही रही कि सागर जिले की 4 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिये 9 मतदान केन्द्रों और दमोह जिले के वार्ड-16 के जनपद सदस्य के निर्वाचन के लिये 9 मतदान केन्द्रों में मतदान इंटिग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीबीएमएस) से कराया गया। इन मतदान केन्द्रों की मतदान प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के सामने तथा सागर और दमोह में एक-एक स्क्रीन लगाई गई इसमें मतदान प्रतिशत सहित अन्य जानकारीयों लोगों ने लाइव देखीं। सागर जिले के मतदान का प्रतिशत 74.61 रहा। सागर जिले के जनपद पंचायत जैसीनगर की ग्राम पंचायत अगरा, औरिया, जनपद पंचायत

खुरई की ग्राम पंचायत मुहासा और जनपद पंचायत राहतगढ़ की ग्राम पंचायत सेमरा-लहरिया के मतदान केन्द्रों में इंटिग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम से मतदान कराया गया। मतदाताओं ने पेपरलेस मतदान प्रक्रिया को बहुत अच्छा कदम बताया और कहा कि वोट डालने में कम समय लागू और आसानी से वोट डाल सके। आईपीबीएमएस प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिये राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव डॉ. सुवेश शाक्य और मुकुल गुप्ता के नेतृत्व में टीम भी गठित की गई थी। उप सचिव संजु कुमारी ने पूरी प्रक्रिया का सतत पर्यवेक्षण कर जरूरी मार्गदर्शन दिया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पेपरलेस बूथ की नवीन पहल की गई है। इस प्रक्रिया में मतदान केन्द्रों में मतदाता और मतदानकर्मियों द्वारा किये जाने वाला पूरा काम डिजिटल माध्यम से किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस नवीन पहल के तहत वर्ष 2024 में भोपाल जिले के बैरसिया तहसील की ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर और रीवा जिले के अतंरला ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिये मतदान सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल वृत्त के अंतर्गत नारियल खेड़ा में बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। छोला जोन प्रबंधक हनीफ सिंहकी ने बताया कि शहर संभाग उत्तर में नारियल खेड़ा निवासी जावेद अली द्वारा मोटर बायपास कर बिजली चोरी की जा रही थी, जिस पर कंपनी द्वारा 03 फरवरी 2025 को प्रकरण पंजीबद्ध कर राशि 6514 रूपए का बिल जारी किया गया था। आरोपी जावेद अली द्वारा कंपनी के छोला जोन के कर्मचारी जितेंद्र सिंह पर प्रकरण बनवाने के भ्रम के चलते सतर्कता दल के साथ अपनी ड्यूटी के दौरान गाली गलौच और मारपीट करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। इसके विरुद्ध कंपनी के छोला जोन प्रबंधक हनीफ सिंहकी ने थाना गौतम नगर में जावेद अली के खिलाफ भारतीय न्याय सहिता (बीएनएस) का धारा 126, 296, 115, 351, 370 में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं के लिए तैयार करें पाठ्यक्रम: मंगुभाई पटेल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को पहचान कर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तैयार करें। उन्होंने प्रदेश में देश विदेश से निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल की सराहना की है। अपेक्षा की है कि निवेश परियोजना क्रियान्वयन के साथ ही उद्योग में रोजगार के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के लिए कोर्स प्रारम्भ करें, जिससे परियोजना शुरू होने के साथ ही आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तर के युवा उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज करेंसी का जमाना है, लेकिन स्किल (कौशल) ही करेंसी है, भारत इसे अच्छी तरह समझता है। इसीलिए हम नवाचार करते हुए कौशल विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मध्यप्रदेश एक



कृषि प्रधान और तेजी से बढ़ता राज्य है। इसीलिए हम खेती की पढ़ाई को सामान्य महाविद्यालयों तक लेकर गए हैं। अगर कोई युवा खेती में करियर बनाना चाहे तो उसे आधुनिक तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों के दायरे विस्तृत होने चाहिए। सभी कोर्स यहां से संचालित



होने चाहिए। राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उक्त विचार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मध्यप्रदेश एड.2047 ‘रोजगार आधारित शिक्षा-रूझान एवं नए आधारित शिक्षा-रूझान एवं नए अवसर’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही है। कार्यशाला का आयोजन

बुधवार को कुशाभाऊ ठकुरे सभागार में किया गया। राज्यपाल पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार आधारित शिक्षा-रूझान एवं नए अवसर कार्यशाला समय की आवश्यकता है। भविष्य की तैयारी का सशक्त मंच है। रोजगार केन्द्रित शिक्षा और विकसित भारत के निर्माण

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारी करें ग्राम भ्रमण एवं रात्रि विश्राम-मंत्री डॉ. शाह

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि अधिकारी शासकीय योजनाओं को संवेदनशीलता से ग्राम स्तर पर लागू करें। ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रात्रि विश्राम भी करें, जिससे जनजातीय समुदाय की वास्तविक समस्याओं को समझ सकें। मंत्री डॉ. शाह मंगलवार को केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं राज्य के जनजातीय कार्य विभाग के समन्वय से जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में ‘आदि कर्मयोगी अभियान = रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम’ के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अभियान के तहत 22 से 28 जुलाई 2025 तक सात दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होटल

रेजन्टा पैलेस आईएसबीटी कैम्पस में किया जायेगा। प्रशिक्षण में उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश से 24 प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अभियान में 12 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण उपरांत 50 जिलों में प्रति जिला 07-07 मास्टर ट्रेनर्स अर्थात कुल 350 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर्स विकासखण्ड स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देंगे, जो आगे ग्राम स्तर के कर्मयोगियों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनजातीय कार्य विभाग सहित स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सभी विभाग आपसी समन्वय से इस अभियान को ग्राम स्तर

तक पहुंचाएंगे। ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को उनके कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को स्वार्थ रहित, पूर्ण निष्ठा एवं संवेदनशीलता से निभाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। शुभारंभ सत्र में केन्द्रीय सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय विभु नायर, उत्तरप्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव वेकेंटेश्वरालू एवं छत्तीसगढ़ सरकार के प्रमुख सचिव सोनमोनी बोराह वरुंचली शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य गुलशन बामरा, केन्द्रीय संयुक्त सचिव अजीत श्रीवास्तव, उप सचिव जफर मलिक एवं आयुक्त सह संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं वंदना वैद्य ने भी संबोधित किया।



मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को दिल्ली में केन्द्रीय पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से निज निवास पर मुलाकात की। मंत्री पटेल ने केन्द्रीय मंत्री सिंह को राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत किए जा

रहे विकास कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने न्यायल योजनाओं में सौर ऊर्जा के उपयोग, व्यापक संचार सम्पर्क, पंचायत भवनों के निर्माण, नवीन पेसा सेल के गठन सहित विभिन्न मुद्दों पर केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की। इस अवसर पर मंत्री पटेल ने कहा कि यह मुलाकात पंचायतों के विभिन्न गतिरोधों का सकारात्मक समाधान देगी।

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर होंगे प्रारंभ-उच्च शिक्षा मंत्री परमार

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में, राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री परमार ने विश्वविद्यालय स्तर प्रशिक्षण शिविर फिर से विश्वविद्यालय की सहयोगिता राशि से प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोदग्राम योजना के विभिन्न पहलुओं को धरातल पर सार्थकता प्रदान करने के निर्देश दिए। मंत्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में प्रत्येक 6 माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। मंत्री परमार ने कहा कि कार्यक्रम अधिकारियों का जिला/विश्वविद्यालय स्तर पर एक या दो दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाये। उन्होंने कहा कि एनएसएस गतिविधियों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायें और इसकी समीक्षा भी की जाये। मंत्री परमार

ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में स्वयंसेवी विद्यार्थियों की सहभागिता को उनके मूल्यांकन में अतिरिक्त वेटेज देने की विश्वविद्यालयों द्वारा कार्य-योजना बनायी जाये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से ग्रामों में रोजगार एवं स्व-रोजगार आदि विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वेक्षण भी कराया जाये। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जब तक 7 दिवसीय प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक जिला/ विश्वविद्यालय स्तर पर एक या दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। परमार ने कहा कि एनएसएस गतिविधियों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं और इसकी समीक्षा विभागीय बैठकों में की जाए। विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना के

माध्यम से ग्रामों में परिणाममुखी क्रियान्वयन करें। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि रासेयो द्वारा किए जाने वाले गोदग्राम गतिविधियों में विद्यार्थियों के मध्य मेरा गोदग्राम सबसे अच्छा नाम से विश्वविद्यालय स्तर पर इकाईयों के मध्य आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराकर उत्कृष्ट ग्राम की रासेयो इकाई को पुरस्कृत करें। राजन ने कहा कि पेड मां के नाम अंतर्गत रासेयो के स्वयंसेवी विद्यार्थियों द्वारा अधिकाधिक पौधरोपण किया जाए। सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने स्कूल शिक्षा में रासेयो इकाईयों की स्थापना के लिए पूर्ण सहयोग देने की बात कही। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव दिनेश जैन ने रासेयो प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के ट्रेनिंग सेन्टर उपलब्ध कराने के लिए सहमति प्रदान की।

संपादकीय

अपाचे हेलिकॉप्टर की सेना में एंट्री, मिग-21 को वायुसेना से विदाई

भारतीय सशस्त्र बलों में इन दिनों दो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं— एक ओर अत्याधुनिक अपाचे II-64श्च अटैक हेलिकाॉप्टर सेना में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक लंबा इतिहास समेटे मिग-21 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना से विदाई ले रहा है। ये दोनों घटनाएं भारतीय रक्षा क्षमताओं में बदलाव का प्रतीक हैं और भविष्य की रणनीतिक दिशा को दर्शाती हैं। हम आपको बता दें कि अपाचे एएच-64ई विश्व के सबसे आधुनिक और प्रभावशाली अटैक हेलिकॉप्टरों में से एक है। अमेरिका द्वारा निर्मित यह हेलिकॉप्टर अब भारतीय थलसेना के पास भी होगा। पहले अपाचे हेलिकॉप्टर केवल भारतीय वायुसेना के बेड़े में थे, लेकिन अब इन्हें सेना को भी सौंपा जा रहा है, जिससे जमीनी अभियानों में जबरदस्त बढ़त मिलेगी। अपाचे की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो आपको बता दें कि यह हेलिकॉप्टर दिन और रात, किसी भी मौसम में ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें हेलफायर मिसाइल, 70 मिमी रॉकेट्स और 30 मिमी की ऑटोमैटिक गन लगी होती है, जो इसे अत्यंत मारक बनाती है। साथ ही अपाचे हेलिकॉप्टर ड्रोन और अन्य विमानों से जुड़कर एकीकृत ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें उन्नत रडार, नाइट विजन और आत्मरक्षा प्रणाली होती है जो इसे दुश्मन की मिसाइलों से बचाती है। भारतीय सेना को कैसे मिलेगा लाभ यदि इसके बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इसके आने से दुर्गम पहाड़ी इलाकों में तेजी से तैनाती और आक्रमण क्षमता बढ़ेगी। आतंकवाद और घुसपैठ विरोधी अभियानों में मजबूती मिलेगी तथा स्वदेशी टैंक रेजिमेंट्स के साथ संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता बढ़ेगी। वहीं अगर मिग-21 की बात करें तो आपको बता दें कि यह भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। इसे वर्ष 1963 में सोवियत संघ से आयात किया गया था। एक समय ऐसा था जब भारतीय वायुसेना के अधिकांश फाइटर स्काइन मिग-21 पर ही आधारित थे। इसकी प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करें तो आपको बता दें कि 1971 के भारत-पाक युद्ध में मिग-21 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। इसके अलावा कारगिल युद्ध और बालाकोट स्ट्राइक जैसे अभियानों में भी इसका उपयोग हुआ था। हम आपको यह भी बता दें कि बीते दशकों में मिग-21 को फ्लाईंग कॉफिन और विधवा बनाने वाला भी कहा गया, क्योंकि इसमें तकनीकी खामियों और रख-रखाव की जटिलताओं के कारण कई दुर्घटनाएँ हुईं। अब जब यह 60 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हो रहा है, तो यह एक युग के अंत की तरह है। अब सवाल उठता है कि मिग-21 के बाद कौन लेगा इसकी जगह? तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना अब पुराने विमानों की जगह नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स ला रही है। इसमें सबसे पहला नाम तेजस का है। यह स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जोकि उच्च गतिशीलता, उन्नत एवियोनिक्स और हथियार प्रणाली से लैस है। तेजस अब मिग-21 का प्राकृतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास अब राफेल है जोकि फ्रांस से आयातित बहुउद्देश्यीय फाइटर जेट है। यह लंबी दूरी की स्ट्राइक, डॉगफाइट और परमाणु हथियारों की तैनाती में सक्षम है। साथ ही अभी विकास के चरण में हैं। भविष्य में स्वदेशी फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट और नेवी फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और नौसेना को और मजबूती देंगे। बहरहाल, अपाचे हेलिकॉप्टरों की तैनाती और मिग-21 की विदाई एक प्रतीकात्मक परिवर्तन है। यह दिखाता है कि भारत अब अपने रक्षा बलों को तकनीकी रूप से उन्नत, अत्याधुनिक और नेटवर्क-सक्षम बना रहा है। जहां मिग-21 ने दशकों तक आसमान में भारतीय शक्ति का प्रतीक बनकर सेवा दी, वहीं अपाचे जैसे नए प्लेटफॉर्म अब ज़मीन पर दुश्मन के मनोबल को तोड़ने का कार्य करेंगे।

एसआईआर की आंच से तपने लगा पश्चिम बंगाल

डॉ. आशीष वशिष्ठ ।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में भी एसआईआर के विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। एसआईआर का मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, लेकिन अभियान की टाइमिंग को लेकर प्रश्न अवश्य उठाए हैं। भारत निर्वाचन आयोग बिहार के बाद, चुनाव आयोग इस वर्ष के अंत तक 2026 में चुनाव होने वाले पांच राज्यों में मतदाता सूचियों की इसी प्रकार की समीक्षा करेगा। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष मई-जून में समाप्त हो रहा है। ध्यान रहे पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में एनआरसी बड़ा मुद्दा है योंकि इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों की बड़ी संया है। पश्चिम बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर बेचैन है तो वहीं कांग्रेस असम को लेकर चिंतित है।



गैर भाजपशासित कई राज्यों से विरोध की आवाज उठने लगी है। हालांकि विरोध का सबसे ऊंचा स्वर पश्चिम बंगाल से सुनाई दे रहा है, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। बीती 21 जुलाई को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा बंगाल में एसआईआर जैसी कवायद करने की योजना बना रही है, इसे कभी अनुमति नहीं दी जाएगी। वास्तव में, ममता के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी ममता एसआईआर को लेकर भाजपा पर राजनीतिक बाण चला रही हैं। भला एसआईआर करवाने या न करवाने से भाजपा का क्या संबंध? सोचिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभी शुरू भी नहीं हुआ, और ममता बनर्जी ने इसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इसी से तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी को समझा जा सकता है।

ममता बनर्जी का सार्वजनिक मंच से यह कहना कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीधे तौर पर चुनाव आयोग को धमकी के साथ संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान भी है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के मन में आदर का भाव बचा ही नहीं है।

सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बनाने से लेकर ईडी के अधिकारियों पर प्राणघातक हमले में प्रदेश सरकार और तृणमूल कांग्रेस की भूमिका जगजाहिर है। अभी हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ बिल के विरोध में ममता ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। भला कोई संविधान के तहत निर्वाचित सरकार और मुख्यमंत्री ऐसे कैसे गैरजिम्मेदाराना संविधान विरोधी बयानबाजी कर सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने नियम कानून और संविधान को शायद खूंटी पर टांग रखा

है। ममता बनर्जी एसआईआर को एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से भी ज्यादा खतरनाक बता चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नेता डेरैक ओ ब्रायन ने बीती 28 जून को कहा कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने का एक भयावह कदम है।' संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया है। तृणमूल कांग्रेस के अलावा कांग्रेस, राजद, सपा और विपक्ष के अन्य दल इस विरोध में शामिल हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की ज़ोरों से चर्चा है कि बिहार के बाद मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की बारी पश्चिम बंगाल की होगी। तभी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बहुत बेचैन है। तृणमूल कांग्रेस को यह चिंता सता रही है कि अगर चुनाव आयोग ने चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में टारगेट करके मतदाताओं के नाम काटे तो उसका फायदा भाजपा को होगा। पश्चिम बंगाल में 30 फीसदी मुस्लिम आबादी है, जिसके बारे में भाजपा आरोप लगाती है कि इनमें बड़ी संख्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या की है। इनका वोट एकमुश्त तृणमूल को जाता है। हर क्षेत्र में 10 से 20 हजार नाम अगर कट जाते हैं तो तृणमूल को उसका बड़ा नुकसान होगा। हालांकि बिहार से उलट पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। वे आसानी से नाम नहीं कटने देंगे। पिछले कई महीनों से वे खुद घर घर जाकर सब चेक कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि पिछले 14 वर्षों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को मतदाता सूची में व्यवस्थित रूप से घुसपैठ कराई है। बीते मार्च पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ऑडिट और मतदाता सूची संशोधन की ज़रूरत से अवगत कराते हुए बताया था कि पश्चिम बंगाल में 13 लाख से अधिक फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता हैं। बीते जून को भाजपा ने दावा किया कि बंगलादेश से जुड़े कोटा सुधार आंदोलन के नेता न्यूटन दास का नाम काकद्दीप विधानसभा इलाके के वोटर लिस्ट में है। तृणमूल ने आरोपों से इनकार किया है। बीते दिनों मालदा जिले के गाजोल के एक गांव में ऐसा मामला सामने आया है, जहां इलाके में एक भी अल्पसंख्यक व्यक्ति नहीं रहता, वहां दो अपरिचित और कथित अल्पसंख्यक वोटरों के नाम नये मतदाता सूची में शामिल पाये गये हैं। इसे लेकर भाजपा विधायक चिन्मय देव बर्मन ने अवैध घुसपैठ और फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया है। बीती जून को सिलीगुड़ी में फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ स्पेशल ऑपरेशन रफ़ू ने किया था। राज्य में अलग-अलग क्षेत्रों से फर्जी वोटर मामले सामने आने के कारण राजनीतिक माहौल और गर्माया हुआ है। ममता बनर्जी ने 'फेक वोटर' की पहचान के लिए एक समिति भी बनाई है।

जानकार मानते हैं कि दिल्ली की जीत के बाद भाजपा की नज़र 2026 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पछाड़ने पर है। दिल्ली चुनाव में मिली जीत से भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो ज्यादा मजबूती से ममता बनर्जी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। ममता बनर्जी भी जमीनी सच्चाई और आने वाले राजनीतिक खतरों को बखूबी भांप रही है। इसलिये उन्होंने अभी से विरोध का स्वर ऊंचा करना शुरू कर दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ईडी गठबंधन के नेता संविधान के सम्मान और रक्षा की बात करते हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का भेद है। वो कदम कदम पर संविधान, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की परंपराओं का अनादर करते दिखाई देते हैं।

एक तरफ, विपक्ष चुनाव आयोग पर भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगाता है। वहीं दूसरी तरफ, जब चुनाव आयोग मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर कर साफ सुथरी सूची बनाने का अभियान चलाता है, तो उसका विरोध करने लगता है। साफ सुथरी वोटर लिस्ट न बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। विपक्ष के इस दोहरे मापकण्ड और चरित्र के बारे में भला क्या कहा जाए। विपक्ष के ऐसे रवैये से एक बात तो साफ है कि विपक्ष चुनाव में मिली हार और अपनी नाकामी छिपाने के लिए चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट और ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ता है? तय मानिए, आने वाले दिनों में एसआईआर के विरोध की गूंज देशभर में सुनाई देगी। और यह भी लिखकर रख लीजिए इसमें सबसे ज्यादा ऊंची आवाज तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की होगी। तृणमूल कांग्रेस के विरोध, धमकी और बेचैनी से यह समझ में आ रहा है कि दाल में कुछ नहीं बहुत कुछ काला है।

ऑनलाइन भुगतान के मामले में भारत के यूपीआई ने अमेरिका के वीजा को पीछे छोड़ा

प्रह्लाद सबनानी

हाल ही के समय में भारत, विभिन्न क्षेत्रों में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नित नए रिकार्ड बना रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो अब भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने बैंकिंग व्यवहारों के मामले में तो जैसे क्रांति ही ला दी है। अभी हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में बैंकिंग व्यवहारों के मामले में भारत के युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने अमेरिका के 67 वर्ष पुराने वीजा एवं मास्टर कार्ड के पेमेंट सिस्टम को प्रतिदिन होने वाले आर्थिक व्यवहारों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक स्तर पर अब भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क बन गया है। भारत में वर्ष 2016 के पहले ऑनलाइन पेमेंट का मतलब होता था केवल वीजा और मास्टर कार्ड। वीजा और मास्टर कार्ड को चलाने वाली अमेरिका की ये दोनों कंपनियां पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट का एकाधिकार रखती थीं। वीजा की शुरुआत, अमेरिका में वर्ष 1958 में हुई थी और धीमे धीमे यह कंपनी 200 से अधिक देशों में फैल गई और ऑनलाइन भुगतान के मामले में पूरे विश्व पर अपना एकाधिकार जमा लिया। वैश्विक स्तर पर इस कम्पनी को चुनौती देने के उद्देश्य से भारत ने वर्ष 2016 में अपना पेमेंट सिस्टम, यूपीआई के रूप में, विकसित किया और वर्ष 2025 आते आते भारत का यूपीआई सिस्टम आज पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। आज सब्जी वाले, चाय वाले, सहायता प्राप्त करने वाले नागरिक एवं छोटी छोटी राशि के आर्थिक व्यवहार करने वाले नागरिकों के लिए यूपीआई सिस्टम ने ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार करने को बहुत आसान



बना दिया है। आज भारत के यूपीआई सिस्टम के माध्यम से प्रतिदिन 65 करोड़ से अधिक व्यवहार (1800 करोड़ से अधिक व्यवहार प्रति माह) हो रहे हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वीजा कार्ड से माध्यम से प्रतिदिन 63.9 करोड़ व्यवहार हो रहे हैं। इस प्रकार, भारत के यूपीआई ने दैनिक व्यवहारों के मामले में 67 वर्ष पुराने अमेरिका के वीजा को पीछे छोड़ दिया है। भारत में केंद्र सरकार की यह सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। भारत अब इस मामले में पूरी दुनिया का लीडर बन गया है। भारत ने यह उपलब्धि केवल 9 वर्षों में ही प्राप्त की है। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह नई तकनीकी का चमत्कार है एवं यह सिस्टम अत्यधिक प्रभावशाली है। भारत का यूपीआई सिस्टम भारत को वैश्विक बैंकिंग नक्शे पर एक बहुत बड़ी शक्ति बना सकता है। भारत में यूपीआई की सफलता की नौव दरअसल केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई कई आर्थिक योजनाओं के माध्यम से पड़ी है। समस्त नागरिकों के आधार कार्ड बनाने के पश्चात जब आधार कार्ड को नागरिकों के बैंक खातों से जोड़ा गया और केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब वर्ग की सहायता के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत

सहायता राशि को सीधे ही नागरिकों के बैंक खातों में जमा किया जाने लगा तब एक सुदृढ़ पेमेंट सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में यूपीआई का जन्म वर्ष 2016 में हुआ। यूपीआई को आधार कार्ड एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंकों में खोले गए खातों से जोड़ दिया गया। नागरिकों के मोबाइल क्रमांक और आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़कर यूपीआई सिस्टम के माध्यम से आर्थिक एवं लेन-देन व्यवहारों को आसान बना दिया गया। भारत में आज लगभग 80 प्रतिशत युवा एवं बुजुर्ग जनसंख्या का विभिन्न बैंकों के खाता खोला जा चुका है।

यूपीआई के माध्यम से केवल कुछ ही मिनटों में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जा सकता है। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में यूपीआई के आने के बाद तो अब भारत के नागरिक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड को भी भूलने लगे हैं। भारत से बाहर अन्य देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक भी अपनी बचत को यूपीआई के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन राशि का अंतरण चंद मिनटों में कर सकते हैं। पूर्व में, बैंकिंग चेनल के माध्यम से एक देश के बैंक खाते से दूसरे देश के बैंक खाते में राशि का अंतरण करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता था तथा विदेशी बैंकों द्वारा इस प्रकार के अंतरण राशि पर खर्च भी वसूला जाता है। अब यूपीआई के माध्यम से कुछ ही मिनटों में राशि एक देश के बैंक खाते से दूसरे देश के बैंक खाते में अंतरित हो जाती है। इससे भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण भी हो रहा है। विश्व के अन्य देशों में पढ़ाई के लिए गए छात्रों को अपने खर्च चलाने एवं

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में फीस की राशि यूपीआई सिस्टम से जमा कराने में बहुत आसानी होगी। जिस भी देश में भारतीय मूल में नागरिकों की संख्या अधिक है उन देशों में भारत के यूपीआई सिस्टम को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज 13,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि इन देशों में निवास कर रहे भारतीय मूल के नागरिकों द्वारा प्रतिवर्ष भारत में भेजी जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत के यूपीआई सिस्टम की स्वीकार्यता बढ़ने से अमेरिकी डॉलर पर भारत की निर्भरता भी कम होगी, इससे भारतीय रुपए की मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी और डीडोलराईजेशन की प्रक्रिया तेज होगी। भारत ने यूपीआई के प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों की संख्या के मामले में आज अमेरिका, चीन एवं पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में भारत के यूपीआई सिस्टम का विश्व के 7 देशों यथा यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रान्स, ओमान, मारीशस, श्रीलंका, भूटान एवं नेपाल में उपयोग हो रहा है। इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक यूपीआई के माध्यम से सीधे ही भारत के साथ आर्थिक व्यवहार कर रहे हैं। दक्षिणपूर्वीय देशों यथा मलेशिया, थाइलैंड, फिलिपींस, वियतमान, सिंगापुर, कम्बोडिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताईवान एवं हांगकांग आदि भी भारत के यूपीआई सिस्टम के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया एवं यूरोपीयन देशों ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में लागू करने की इच्छा जताई है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस एवं नामीबिया यात्रा के दौरान इन दोनों देशों ने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में शुरू करने के लिए भारत से निवेदन किया है।

नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर ने पचमढ़ी पहुंचकर नागद्वारी मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

नर्मदापुरम (एजेंसी)। नागद्वारी मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने सोमवार को नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) मिथिलेश कुमार शुक्ला के साथ पचमढ़ी पहुंचे। कमिश्नर ने नागद्वारी मेले में श्रद्धालुओं को दी जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। और श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। कमिश्नर तिवारी ने एसडीएम पिपरिया अनंषा श्रीवास्तव को निर्देश दिये कि नागद्वारी जाने वाले मार्ग पर अनावश्यक रूप से वाहनों का जाम न लगे। यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद रहे। श्रद्धालुओं को कदम कदम पर पेयजल एवं टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध रहे। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी विभिन्न पाइंट पर लगाई गई है वे सभी अधिकारी एवं



कर्मचारी निभ्रारित समय पर अपने पाइंट पर उपस्थित रहे एवं श्रद्धालुओं को आ रही समस्याओं एवं कठिनाईयों का मौके पर रहकर निराकरण करें। कमिश्नर एवं पुलिस महानिरीक्षक ने जलगली मार्ग पर

बनाये गये स्वास्थ्य विभाग के एवं पुलिस सहायता केन्द्र के पाइंट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अब तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा काउंटर से लाभान्वित होने वाले

श्रद्धालुओं की जानकारी ली और उपस्थित चिकित्सकों एवं चिकित्सा स्टॉफ को श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की दवायें एवं औषधि का स्टॉक रखने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि मौसम के मद्देनजर होने वाली सर्दी खांसी उल्टी दस्त आदि का उपचार चिकित्सा काउंटर पर दवाईयां देकर कर दिया जाए वहीं मरीज की मौसम के अनुसार गंभीर स्थिती होने पर उसे तत्काल पचमढ़ी य पिपरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर किया जाए। कमिश्नर तिवारी ने जलगली मार्ग पर बनाये गये पुलिस सहायता केन्द्र का भी अवलोकन किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बताया कि अभी तक किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था की घटना सामने नहीं आई है।

पुलिस कर्मी हर अग्रिय स्थिती से

रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से टीबी रोगियों को मिली फूड बास्केट

हरदा (एजेंसी)। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने क्षय रोगियों के लिए पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से फूड बास्केट उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला चिकित्सालय हरदा में आयोजित कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉ. एच.पी. सिंह ने रोगियों को फूड बास्केट का वितरण किया। इस अवसर पर डॉ सिंह ने बताया कि टीबी एक गंभीर संक्रमण है जो शरीर को बहुत कमजोर कर देता है। टीबी के जीवाणु शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, जिससे मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है।

अच्छ पोषण प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे शरीर बीमारी से लड़ने और ठीक होने में बेहतर तरीके से सक्षम हो पाता है। कार्यक्रम में आसपास के ग्रामों एवं हरदा नगर से आए मरीजों व उनके परिजनों ने टीबी यूनिट के प्रयासों की सराहना की व रेडक्रॉस सोसायटी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला मूल्यांकन अधिकारी मनीष शकरगाए, डीआईएम आशीष साकहे, टीबी यूनिट से नीता चौबे, ब्रजेश थापक, राघव गुहा, ममता गुहा, बलराम विश्वकर्मा उपस्थित थे। जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉ. मृत्युंजय सिंह गहलोत ने बताया कि कलेक्टर

सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में टीबी मुक्त भारत अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। कलेक्टर जैन के निर्देश पर विशेष अभियान चलाते हुए जिले के 1 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है तथा लक्षण चिन्हों के आधार पर दस हजार लोगों के बलगम की जांच अत्याधुनिक मशीन के द्वारा की गई। डॉ. गहलोत ने बताया कि गांव गांव में विशेष शिविर लगाकर ढाई हजार लोगों को छाती का एक्स-रे विशेष जांच शिविर जिले के दूरस्थ ग्रामों से लेकर सभी नगरीय क्षेत्र में निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनी नागरिकों की समस्याएं



हरदा (एजेंसी)। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित 'जनसुनवाई' कार्यक्रम में आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उपस्थित अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के

निराकरण के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित 'जनसुनवाई' कार्यक्रम में आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उपस्थित अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के

निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय एवं संजीव नागू के साथ-साथ एसडीएम टिमरनी महेश बड़ोले, एसडीएम खिरकिया अशोक डहेरिया सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी मौजूद थे। जनसुनवाई में ग्राम बालागांव निवासी सीमा गौर ने कलेक्टर जैन को आवेदन देकर मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर उन्होंने तहसीलदार हरदा को आवेदिका को समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में ग्राम जामली निवासी रामकृष्ण पवार ने कलेक्टर जैन को आवेदन देकर पांचातलाई से

सालाबैड़ी मार्ग की चयनेज पुलिया को बनाने की मांग की, जिस पर उन्होंने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को आवेदक की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में ग्राम मुहाड़िया निवासी संतोष पायशर ने कलेक्टर जैन को गरीबी रेखा का कूपन कर्मकार मण्डल का कार्ड बनाने के लिये आवेदन दिया, जिस पर उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदक की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में ग्राम भुन्नास निवासी चन्द्रेश गौर ने कलेक्टर जैन को आवेदन देकर बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम भुन्नास से लेकर सरस्वती स्कूल हरदा तक नवीन रोड़ का निर्माण कार्य चल रहा है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत माखननगर एवं सोहागपुर परियोजनाओं में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

नर्मदापुरम (एजेंसी)। कलेक्टर सोनिया मोना के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 15 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष पंजीयन अभियान के अंतर्गत सोमवार को जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमन, नर्मदापुरम के माध्यम से परियोजना माखननगर एवं परियोजना सोहागपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर योजना के हितग्राही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शौर्य दल सदस्य



एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सीमा मेहरा, सहायक निदेशक, आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना

स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को मिलने वाली सहायता सेवाओं की जानकारी भी साझा की गई। कार्यक्रम में हेमंत पंथी, जिला समन्वयक, पोषण अभियान द्वारा पोषण ट्रेकर एप के माध्यम से हितग्राहियों के फेस कैप्चर और ऐप के उपयोग संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर माखननगर एवं सोहागपुर परियोजनाओं के सेक्टर पर्यवेक्षकगण भी उपस्थित रहे तथा उन्होंने स्थानीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु सहयोग प्रदान किया।

वर्षा से हुई जनहानि में आरबीसी 6/4 के तहत पीड़ितों को तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए - कमिश्नर

नर्मदापुरम (एजेंसी)। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वह वर्षा से होने वाली जनहानि में पीड़ितों को तत्काल आरबीसी 6/ 4 के तहत राहत राशि देना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि जनहानि की घटना और राहत राशि देने के बीच अनावश्यक विलंब न किया जाए। उन्होंने नर्मदापुरम हरदा और बैतुल जिले के कलेक्टर से तत संबंध में हुई अब तक कार्रवाई की जानकारी ली। नर्मदापुरम कलेक्टर ने बताया कि नर्मदापुरम जिले में 6 व्यक्तियों की डूबने से एवं पांच व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हुई। जिनमें राहत राशि देने के प्रकरण बनाए गए हैं बैतुल कलेक्टर ने बताया कि पांच व्यक्तियों की डूबने से एवं अन्य की अन्य कारणों से मृत्यु हुई है जिसमे राहत राशि दे दी गई है। वही हरदा कलेक्टर ने बताया कि हरदा जिले में अभी तक वर्षा से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कमिश्नर ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे मृग उपाजर्जन एवं भुगतान के बीच ज्यादा गैप न रखें। किसानों को मृग उपाजर्जन का भुगतान जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा की भुगतान में जल्दी से अग्रिय स्थिति से बचा जा सकता है।



कमिश्नर ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में हितग्राहियों के केवाईसी कराई जाए, जो डेड खाते हैं वो बंद कराए जाए। साथ ही जन धन खाते भी खुलवायें जाए। अटल पेंशन के नए हितग्राहियों का पंजीयन भी प्राथमिकता से किया जाए, इसके लिए उन्होंने तीनों जिलों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये। कमिश्नर तिवारी ने मनरेगा अंतर्गत एक बागिया मां के नाम अभियान की समीक्षा की। बताया गया की एक बागिया मां के नाम अभियान में एक एकड़ की निजी भूमि पर भूमि मालिक को बागिया डेवलप करना है। इसके लिए हरदा

बेतुल एवं नर्मदापुरम जिले में हितग्राहियों का चिन्हाकन हो गया है। हितग्राहियों की ट्रेनिंग भी कराई गई है। बताया गया की नर्मदा नदी के किनारे एक वृक्ष लगाने का अभियान भी प्रगति पर है। इसके लिए नर्मदा किनारे आश्रय स्थल भी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। लार फेंसिंग एवं प्लांटेशन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। कमिश्नर तिवारी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये की वे आंगनबड़ी केन्द्रों में टॉयलेट, बागिया, रेन वॉटर सिस्टम आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने नजूल लीज नवीनीकरण के प्रकरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये की घर-घर संपर्क कर लीज धारी व्यक्तियों को लीज खतम होने की

सूचना देकर नवीन नजूल लीज का नवीनीकरण करने की समझाईश देने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने शासकीय भवनों, छात्रवास, स्कूल कॉलेज, एवं अन्य विभागीय भवन बनाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिये। और कहा की जहां जहां भूमि आवंटन आसानी से हो रहा है वहां पहले भूमि आवंटन कर दिया जाए। कमिश्नर तिवारी ने जिले में आगामी अगस्त माह में आने वाले पर्व एवं त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद रखने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने नागद्वारी मेला, मृग उपाजर्जन, खाद वितरण व्यवस्थित रूप से करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने नर्मदापुरम के हर्बल पार्क, एवं आंवली घाट तथा अन्य घाटों में लोगों के डूबकर होने वाली घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिये की इन घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी घाटों पर चेतावनी बोर्ड अनिवार्य से लगाए जाए। कमिश्नर ने चिन्हित स्कूलों के जर्जर भवनों को डिस्मैटल करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने ई ऑफिस सिस्टम के तहत सभी शासकीय कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा की ई ऑफिस सिस्टम में यदि फाइलों में गलतियां हो रही है तो रेमिंगटन गेल सीबीआई पर टाईपिंग कर त्रुटियों को सुधारा जाए।

सीईओ जिला पंचायत अक्षत जैन ने भीमपुर सीएससी का किया निरीक्षण

बैतुल (एजेंसी)। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन ने मंगलवार को भीमपुर निरीक्षण के दौरान चिखली के गोडकों ढाना गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में जमीन पर बैठकर एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीयता भरी बैठक की। बैठक में जैन ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति को समझा, बल्कि कार्यकर्ताओं की परेशानियों, सुझावों और अनुभवों को भी पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना। इस दौरान सीईओ जैन ने क्षेत्र में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाओं की समीक्षा की। सीईओ जैन ने ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल्स और पंजी रजिस्ट्रियों की भी जांच की और उनमें सुधार के लिए संबंधित कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। जिला पंचायत के मुख्य

कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन ने भीमपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लेबर रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा बर्थ वेटिंग एरिया और केएमसी कॉनर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीईओ जैन ने चिखली के गोडकी ढाना ग्राम में आयोजित वीएचएनडी टीकाकरण कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। साथ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच संबंधी कार्यों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. प्रांजल उपाध्याय, बीएमओ डॉ. पंकज उडके, बीपीएम तिवारी मोरले, सीडीपीओ रामबाई तथा अंतरा फाउंडेशन से डॉ. सोनू राय सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।



संभागायुक्त 23 जुलाई को लेंगे विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक

नर्मदापुरम। संभागायुक्त नर्मदापुरम के जी तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार 23 जुलाई 2025 को प्रातः10-30 बजे से संभागायुक्त कार्यालय नर्मदापुरम संभाग के सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग, अनुसूचित जनजाति विकास एवं जनजातीय कार्य विभाग, (अंत व्यवसायी विकास निगम, आदिवासी वित्त विकास निगम सहित), उच्च शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं पेंशन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने विभागीय कार्यों की अद्यतन जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम

1961 पर कार्यशाला का आयोजन

नर्मदापुरम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के प्रावधानों की जानकारी के लिए एत दिवस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, नर्मदापुरम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक श्रमायुक्त रजनी मालवीय द्वारा अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी कार्यशाला में उपस्थित बस ऑपरेटरों को दी गई। उन्होंने बताया कि नियोजकों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने वाहनों एवं कर्मकारों का पंजीयन कराना अनिवार्य है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रिकू शर्मा ने सभी ऑपरेटरों से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के परिपालन में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं और अधिनियम के तहत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कार्यशाला के दौरान राजेश फौजदार ने जानकारी दी कि उनकी सभी बसों में व्हीलक ट्रैकिंग सिस्टम की व्यवस्था पहले से की गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कार्यशाला में श्रम पदाधिकारी वर्षा इरपाचे, श्रम निरीक्षक ज्योति पी.ए., सुसरिता साहू, राकेश फौजदार, संजय शिवहरे, राजेंद्र तोमर, मनीष तिवारी, राजेंद्र सिंह, उमेश गोयल, रामपाल चौधरी, देवेन्द्र एवं सागर सहित अन्य बस संचालक व परिवहन क्षेत्र से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

सर्वोत्तम किसानों व कृषक समूहों को पुरस्कृत किया जाएगा

हरदा। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम “आत्मा” के तहत जिले में विकासखण्ड स्तरीय प्रति कृषक पुरस्कार 10 हजार रुपये तथा जिला स्तरीय सर्वोत्तम प्रति कृषक पुरस्कार 25 हजार रुपये के लिये उन्नतशील कृषकों एवं समूहों से आवेदन पत्र 20 अगस्त तक आमंत्रित किये गये हैं। उपसंचालक कृषि जे.एल. कास्दे ने बताया कि वर्ष 2024-25 में किसानों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीक, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि अभियांत्रिकी में उपज एवं उत्पादकता के आधार पर पृथक-पृथक प्रति विकासखण्ड 5 सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार एवं 10 जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार दिये जायेंगे। कृषकों को आवेदन-पत्र कार्यालयीन समय में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय हरदा, टिमरनी एवं खिरकिया से निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें : कलेक्टर

आमजन को प्राप्त होने वाली राजस्व संबंधी सेवाओं का नियत समय में लाभ दिलाना सुनिश्चित करें : कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्टर ऋप्रतिभा पाल की अध्यक्षता में जिले के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करते हुए आमजन को राजस्व संबंधी सेवाओं का लाभ नियत समय सीमा में दिलायें। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी राजस्व न्यायालय व कार्यालय समय पर खुले। लोगों के न्यायालयीन प्रकरणों की नियमित सुनवाई की जाय तथा राजस्व से संबंधित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण हो। उन्होंने कहा कि राजस्व के प्रकरण 3 माह से अधिक लंबित नहीं रहने चाहिए। सभी तहसीलदार पूर्व के लंबित प्रकरणों का 15 दिवस में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने नामांतरण के समय सीमा से अधिक दिनों तक लंबित प्रकरणों में संबंधित नायब तहसीलदारों को नोटिस देने तथा समय सीमा से अधिक दिनों से लंबित सेवाओं के लिये संबंधितों पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के



निर्देश बैठक में दिये गये।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदाओं में प्रकरणों का परीक्षण कर एसडीएम को तत्परता से निराकृत कर

संबंधितों को सहायता राशि प्रदाय करने के निर्देश दिये। उन्होंने आरसीएमएस में 2 से 5 वर्ष के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर अभिलेख सुधार के प्रकरणों में त्वरित

कार्यवाही किये जाने की बात कही। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि सभी तहसील एक ग्रेड में रहे तथा 50 दिनों से अधिक दिनों से

लंबित शिकायतों का निराकरण करें तथा जिले में संचालित हो रहे शिविरों में भी निराकरण करायें। उन्होंने सवाद से समाधान कार्यक्रम में बटवारा प्रकरणों का मौके पर निराकरण करने के निर्देश दिये।

बैठक में जनसुनवाई के प्रकरणों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये। उन्होंने जिले में फर्मर रजिस्ट्री में अपेक्षित प्रगति न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा तत्परता से कार्य किये जाने के निर्देश दिये। भूअर्जन के संबंध में संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। उन्होंने मगनवा एवं सिमौर के तहसील भवन निर्माण के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में दिये। इस दौरान अपर कलेक्टर क्रसपना त्रिपाठी, समस्त एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, जिला प्रबंधक ईगवर्नेस आशीष दुबे, जिला प्रबंधक लोक सेवा रविकांत पाण्डेय सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

हेमू कालानी की 30 फिट ऊंची प्रतिमा स्थापित करवाने महापौर को सौंपा स्मरण पत्र



सतना। राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था भारतीय सिन्धू सभा द्वारा बुधवार को अमर शहीद हेमू कालानी जन्मोत्सव के अवसर पर म.प्र., सिन्धी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में आयोजित कवि सम्मेलन के अवसर महापौर योगेश ताम्रकार ने हेमू कालानी पार्क परिसर में 30 फीट ऊंची अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा स्थापित करवाने की घोषणा की थी। संस्था के महामंत्री विनोद गेलानी ने बताया प्रतिमा स्थापित करने के लिए संस्थाध्यक्ष अशोक चांदवानी जी के सानिध्य में एक प्रतिनिधिमंडल ने

सौजन्य भेंट की। जिसमें महापौर ने अति शीघ्र प्रतिमा स्थापित करवाने का आश्वासन देते हुए कहा अमर शहीद हेमू कालानी की शहीदी दिवस के पूर्व स्थापित करवाने का प्रयास करूंगा। स्मरण पत्र की एक प्रति वार्ड पार्श्व एवं लोक निर्माण अध्यक्ष गोपी गेलानी जी को भी प्रेषित की गई। इस अवसर पर प्रदेश कार्य सदस्य श्री मनोहर आरतानी अध्यक्ष अशोक चांदवानी महामंत्री विनोद गेलानी मंत्री संजय वाधवानी दिलीप सोनी हीरा सोनी मनीष सदानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

मझगवां सीएचसी में तोड़फोड़ करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, शराब के नशे में मचाया था उत्पात

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले के मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में शनिवार देर रात तोड़फोड़ करने वाले दो युवकों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी भट्टन टोला मझगवां के रहने वाले हैं और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान की गई।

सीएचसी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में युवकों की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई थीं। पुलिस ने फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की और फिर उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम अभिषेक कुशवाहा पिता राममनोहर कुशवाहा (21 वर्ष) और विकास कोल पिता रामकेश कोल (21 वर्ष) हैं।

शराब के नशे में किया उत्पात: पुलिस के अनुसार, यह घटना 20 और 21 जुलाई की



दरम्यानी रात करीब 1 बजे की है। दोनों आरोपी शराब के नशे में सीएचसी मझगवां पहुंचे और वहां तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। अस्पताल की संपत्ति को नुकसान

पहुंचाया गया।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर भेजा गया थाने: घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने मझगवां थाना पुलिस को

शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

ग्रामीणों ने शुरू किया जलसत्याग्रह अमिलिया में 5 दिन से ट्रांसफॉर्म खराब; कंपनी ने शिकायत के बाद भी नहीं सुधरवाया

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। ग्राम पंचायत लालपुर के अमिलिया गांव में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। गांव का एकमात्र ट्रांसफॉर्मर पिछले पांच दिनों से खराब है। ग्रामीणों ने 18 जुलाई को ही बिजली विभाग को इसकी सूचना दी थी। लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने बुधवार से तालाब में उतरकर जलसत्याग्रह शुरू कर दिया है। उमस भरी गर्मी में बिजली न होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नया ट्रांसफॉर्मर लगाने तक जारी रहेगा प्रदर्शन: आंदोलन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़ि हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक नया ट्रांसफॉर्मर नहीं लगेगा, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई



की मांग भी की है।

बिजली विभाग की ओर से नहीं मिला जवाब जिला पंचायत सदस्य विमला कोल भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंची हैं। उन्होंने

पहले भी जिला पंचायत के सदन में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। बिजली विभाग की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

होटल मालिक की पत्नी से मारपीट कैमरे में कैद, मामला दर्ज

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले के चित्रकूट में महिला के साथ घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी को जमीन पर गिराकर लात मारते हुए और बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाता हुआ दिख रहा है। यह वीडियो 19 जुलाई का बताया गया है, जो कि घर के अंदर का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को सज्जन में लिया और जांच शुरू की। फुटेज में दिख रहा व्यक्ति चित्रकूट में दो होटलों का मालिक है।

वीडियो के आधार पर 151 के तहत मामला दर्ज: चित्रकूट थाना प्रभारी डीआर शर्मा ने बताया कि महिला या उसके परिवार की ओर से

अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने वायरल



वीडियो के आधार पर धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया है।

महिला ने पति के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया: पुलिस ने वीडियो में दिख रहे स्थान की पहचान कर मौके की पुष्टि की है। महिला ने पति के खिलाफ किसी भी तह तक कार्रवाई से इनकार कर दिया। दोनों का एक पांच साल का बेटा है, जिसे कैसर है।

राज्यमंत्री ने किया सड़क एवं गेट निर्माण कार्य का भूमिपूजन



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिभा बागरी ने बुधवार को ग्राम सुहौला में भर्ती के मध्य लघु निर्माण मद द्वारा स्वीकृत 93.07 लाख रुपये की लागत से बनने वाले रफ्टा, स्टॉप डेम तक पहुंच मार्ग एवं गेट निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। राज्यमंत्री ने कहा कि काराये जा रहे विकास कार्य नागरिकों की सुविधा और

क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनता के विश्वास और सहयोग से रंगांव विधानसभा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा संकल्प है। इस मौके पर सीईओ जनपद पंचायत सोहावरल प्रतिपाल बागरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी तथा बडी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

सवा करोड़ की सड़क दो साल में जर्जर सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया विकास का ट्रेडमार्क, बोले- विकास सड़क फाड़कर निकल रहा



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। एक पुलिसिया सोशल मीडिया पर जमकर टोल हो गई है। दरअसल ग्रामीण विकास यात्रिकी से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जो बेहद ही रोचक है और जिसे लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रीवा में यह तस्वीर इन दिनों चर्चा का विषय बन गई। कोई इस तस्वीर को देश में ग्रामीण विकास का ट्रेडमार्क बता रहा है तो कोई कह रहा है कि विकास सड़क फाड़ कर निकल रहा है। रीवा के मगनवा विधानसभा क्षेत्र में हिनोता गोधाम के पास निर्मित सड़क और पुलिसिया की खस्ता हालत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ग्रामीण विकास यात्रिकी विभाग द्वारा क्यौंटी कटरा मुख्य मार्ग से हिनौती गदही गोशाला तक निर्मित यह सड़क मात्र दो वर्ष में ही जर्जर हो गई है।

सवा करोड़ रुपए में बनी चार किमी लंबी सड़क: चार किलोमीटर लंबी इस सड़क का

निर्माण सवा करोड़ रुपए की लागत से ठेकेदार पुष्पराज सिंह द्वारा किया गया था। विभाग द्वारा निर्माण कार्य का पूरा भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन सड़क की दयनीय स्थिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस निर्माण कार्य को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ यूजर्स इसे ग्रामीण विकास का 'ट्रेडमार्क' बता रहे हैं तो कुछ इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण। स्थानीय निवासी कृष्णा सिंह हिनौती ने कहा कि यह गोशाला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिस पर गांवशों के लिए वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं है।

लोगों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप: सोशल मीडिया यूजर शिवानंद द्विवेदी ने रीवा में सिविल कंस्ट्रक्शन कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अन्य यूजर्स ने भी इस तरह की घटिया गुणवत्ता वाले निर्माण कार्यों पर चिंता जताई है।

न्यायाधीशगणों द्वारा किया गया बालकों को जागरूक

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में तथा जिला न्यायाधीश डॉ. क्रअंजली पारे और न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में ज्ञानस्थली सौनियर सेकेण्डरी स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि क्रअंजली पारे ने बच्चों को लैंगिक

अपराधों से संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पाक्सो अधिनियम में बालक एवं बालिकाओं के यौन शोषण करने वाले अपराधियों के लिये तीन वर्ष से लेकर मृत्युदण्ड तक का प्रावधान है।

सिविल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने उद्बोधन में कहा कि बालकों कि सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण में उनका विकास होना समाज का दायित्व है। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम,

नवांकुर संस्था की आदर्श नर्सरी में तैयार किए गए 1800 पौधे

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जन अभियान परिषद द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों के सहयोग से वृक्षारोपण किया जा रहा है। जन अभियान परिषद से जुड़े स्वसहायता समूहों तथा नवांकुर संस्थाओं ने वृक्षारोपण के लिए बड़ी संख्या में पौध तैयार किए हैं। इस संबंध में संपागीय समन्वयक प्रवीण पाठक ने बताया कि रीवा जिले के गंगेव विकासखण्ड में नवांकुर संस्था माँ बम्बा देवी सामाजिक समिति द्वारा विभिन्न प्रजातियों के 1800 से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं। इन पौधों को ग्राम बेल्वा पैकान में आदर्श नर्सरी में तैयार किया गया है। इन पौधों के रोपण के लिए तैयारियों की जा रही है। हरियाली अमावस्या में नवांकुर संस्था से जुड़ी महिलाओं द्वारा हरियाली यात्रा निकालकर इन पौधों का समारोह पूर्वक रोपण किया जाएगा।

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, अभियान के तहत नगर पालिक निगम सतना के तत्वावधान में ई.धर्मद सिंह परिहार ने सतना शहर को स्वच्छ,सुंदर,स्वस्थ शहर बनाने एवं 4 आर- कचरे को रीड्यूस,रीयूज,रीसाइकिल,रिफ्यूज की अवधारणा के साथ, होमकंपोस्टिंग, पर्यावरण संरक्षण", "मतदाता जागरूकता", "स्वच्छता जागरूकता", "नशा मुक्ति", "अपराध मुक्त समाज", "भ्रष्टाचार मुक्त समाज", की परिकल्पना के साथ स्काई जिम सेमरिया चौराहा सतना में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सभी से सतना को स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान दिलाने में अपनी अपनी सहभागिता निभाने का अनुरोध किया गया तथा



कचड़ा चार भागों में गीला,सूखा,सेनेटरी तथा घरेलू हानिकारक अलग-अलग -निर्धारित हरी डस्टबिन व नीली डस्टबिन में गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक कचड़ा कलेक्शन (मांगने

वाली) गाड़ी को देने का अनुरोध किया गया। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी से आगामी भविष्य के सभी चुनौतियों के स्वतंत्र,निष्पक्ष, समावेशी,प्रलोभन रहित सुगम,

सहभागी,सुरक्षित होने का प्रयास सर्वजन द्वारा हो ; साथ ही सभी उपस्थित मतदाताओं से निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में

अपने मताधिकार के प्रयोग का अनुरोध किया गया।

कार्यक्रम में शक्ति सिंह डायरेक्टर, योगेश जैन, गुड्डू , ऋषि वाधवानी, कृष्णा कापडी, ईशान, गोवर्ध राजपाल, चिराग, ज्ञानू विक्वर्कमा, नीरज नाथानी, विशाल आहूजा, रॉकी बग्गा,संदीप वाधवानी, कृष् गिलानी,आशीष चौरीसिया,अनु तीर्थवानी, नेहा, सनी, शिवांगी, साक्षी,राकेश नाथानी आदि अनेक लोगों ने भाग लिया। सभी से सिलाल यूज पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने का अनुरोध किया गया। मतदाता शपथ दिलवाई तथा सभी से नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज के प्रयास का संकल्प दिलाया गया।

जिला अस्पताल में आशा वर्कर्स का रेस्ट रूम बना कबाडखाना

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया रेस्ट रूम अब कबाडखाने में तब्दील हो गया है। भारत सरकार ने 2018 में डिलीवरी प्लाईट्स पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए रेस्ट रूम की सुविधा दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला चिकित्सालय में हार्ड डिपेंडेंसी यूनिट के सामने बनाए गए इस रेस्ट रूम का उपयोग कबाड रखने के लिए किया जा रहा है। जिला अस्पताल में रोजाना औसतन 25 से 30 आशा कार्यकर्ताएं गर्भवती महिलाओं के साथ आती हैं। मदर्स वेटिंग एरिया में उनके ठहरने की वैकल्पिक व्यवस्था: कई आशा कार्यकर्ताएं 80 किलोमीटर की दूरी से मरीजों को लेकर आती हैं। रेस्ट रूम के अनुपयोगी होने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने मदर्स वेटिंग एरिया में उनके ठहरने की वैकल्पिक व्यवस्था की है। ये एरिया मूल रूप से उन माताओं के लिए है जिनके बच्चे एसएनसीयू में भर्ती हैं। डेढ़ करोड़ रुपए के नवीनीकरण की मंजूरी मिल चुकी: आरएमओ डॉक्टर शरद दुबे के अनुसार, रेस्ट रूम की स्थिति जर्जर है। आरकेएस की बैठक में डेढ़ करोड़ रुपए के नवीनीकरण की मंजूरी मिल चुकी है। प्रबंधन आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक वातानुकूलित कमरा बनाने की योजना बना रहा है।